महादलितों के मकान के लिए एक्शन प्लान

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

जमीन आवंटन के बावजूद मकान बनाने में नाकाम महादलित परिवारों के लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। इसके लिए विशेष कमेटी बना दी गई है। बुधवार को महादलित विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त फूल सिंह होंगे। महादलितों से संबंधित योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए विकास मित्रों को किसी अन्य कार्य में लगाए जाने पर रोक लगा दी गई है। बैठक में तीन हजार महादलित टोलों में सामुदायिक भवन बनाने और वहां सोलर लैम्प व टेलीविजन सेट का भी निर्णय लिया गया। सभी अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यालयों में जूडो-कराटे का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिस महादलित परिवार को जमीन आवंटित हो चुकी है और जिनका मकान नहीं बना है, वैसे परिवारों के मकान बनवाने के लिए विकास आयुक्त फूल सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। वे राजस्व विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सी. अशोकवर्द्धन और ग्रामीण विकास सचिव अमृत लाल मीणा के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक महादलित परिवार को जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य हर हाल में इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद एससी-एसटी कल्याण सचिव एस.एम. राजू ने बताया कि विकास मित्र महादलित परिवारों और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। डीएम या अन्य पदाधिकारी किसी भी विकास मित्र से महादलित परिवार के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में नहीं लगाएंगे। हर महादलित टोले

सीएम ने की समीक्षा

- विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी
- तीन हजार महादलित टोलों में बनेगा सामुदायिक भवन
- अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यालयों में जूडो-कराटे का प्रशिक्षण

में फलदार वृक्ष लगाया जायेगा। दो सौ फलदार वृक्ष लगाने पर एक मानक दिवस के रूप में माना जाएगा। इसमें चार महादलित परिवार संलग्न रहेगा। महादलित परिवार तीन सालों तक इसका देखभाल करेंगे। तीन साल के बाद एक महादलित परिवार को बीस फलदार पेड़ का पट्टा दिया जाएगा। शीशम और सखुआ जैसे पेड़ों के बीस साल के बाद सूखने पर लकड़ी पर महादलित परिवार का हक होगा। श्री राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दशरथ मांझी कौशल विकास योजना से 40 हजार से ज्यादा लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया है। महादलित टोलों में तीन हजार सामुदायिक भवन के निर्माण की जिम्मेदारी विकास मित्र, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी और जिला कल्याण पदाधिकारी को दी गई है। हर सामुदायिक भवन में ब्रेडा के माध्यम से सोलर लैम्प लगाए जाएंगे। वैसे सामुदायिक भवन जहां सेल्फ हेल्फ ग्रुप सशक्त है, वहां एक टीवी सेट भी लगाया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 62.12 करोड़ रुपये की लागत से 15.20 लाख लाभान्वितों को रेडियो दिया जाएगा। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी, विकास आयुक्त फूल सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को 'विमर्श' में महादलित विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री जीतनराम मांझी, विकास आयुक्त फूल सिंह, प्रधान सचिव अंजनी सिंह।